प्रसंगशः

आलोक मेहता

परमाणु बिजली के साथ मौत का सौदा

न भूलें चेरनोबिल कांड से मरते हजारों लोग और जर्मनी द्वारा परमाणु बिजली से तौबा

एक बार फिर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योग्य सलाहकारों ने जयकार के बीच अपनी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री की यात्रा सफल, क्योंकि जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने भारत के परमाणु बिजली कार्यक्रम या अमेरिका के साथ हुए समझौते का सीधा विरोध नहीं किया। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना-चौगुना करने के लिए भारत सरकार ने हनोवर व्यापार मेले में जर्मन उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि आने वाले वर्षों में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने से औद्योगिक बस्तियां चमचमाने लगेंगी। हर राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता केंद्र का जयघोष हमारे देश में इस तरह होता है कि इन केंद्रों की गड़बड़ियों, कमियों और गंदगियों की ओर लोग ध्यान ही नहीं देते। यदि कोई मेधा पाटकर, अरुंधति राय या प्रवीण तोगड़िया भारत में, अथवा जर्मनी में सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी ग्रीन पार्टी के पर्यावरणवादी कार्यकर्ता एक-दो प्रदर्शन कर देते तो शायद हमारे शक्तिशाली टीवी चैनल और अखबार कुछ सुर्खियां बना देते। इसलिए बहुत लोगों (संभव है, प्रधानमंत्री के सलाहकारों सहित) का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि जब भारत के शीर्षस्थ नेता दुनिया भर में अपने प्रस्तावित परमाणु बिजलीघरों और अंतर्राष्ट्रीय सौदों का ढोल पीट रहे हैं, तब रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जर्मनी सहित अनेक अभिन्न मित्र राष्ट्र 20 साल पहले (26 अप्रैल, 1986) चेरनोबिल परमाणु बिजलीघर में हुई विनाशकारी दुर्घटना को याद करते हुए अब भी हजारों लोगों के कैंसर प्रभावित होने की स्थिति पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। भारत सरकार के विद्वतम विद्वान सलाहकारों ने जर्मनी के मेले और वार्ताओं की अवधि मात्र तीन दिन रहने से इस बात की पड़ताल करने का समय नहीं निकाला होगा कि जर्मनी ने अगले 15 वर्षों में धीरे-धीरे अपने सभी 17 परमाणु बिजली संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया हुआ है। यह निर्णय आज चेरनोबिल दुर्घटना की याद में नहीं हुआ है। जर्मन सरकार और संसद ने बाकायदा बिजली उद्योग से जुड़े लोगों और अन्य पक्षों को विश्वास में लेकर सन 2000 में ही यह कानूनी व्यवस्था कर दी कि पर्यावरणीय तथा जनहित की रक्षा के लिए परमाणु बिजली संयंत्रों को बंद किया जाएगा और ऊर्जा के वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे। निश्चित रूप से इस कड़े निर्णय से कुछ राजनीतिक दल और संगठन सहमत नहीं रहे हैं और अब भी आवाज उठाते रहते हैं। विश्व बैंक और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से अभिभूत भारत के शीर्ष नेता (कांग्रेस ही नहीं, भाजपा गठबंधन के भी) परमाणु बिजली की अनिवार्यता समझाते नहीं थकते हैं लेकिन असली तथ्य यह है कि पूरी दुनिया में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों में केवल 16 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता है। विश्व में अब तक केवल 444 परमाणु बिजली संयंत्र हैं, जिनमें 204 यूरोप में हैं। विरोध-समर्थन के बीच विभिन्न देशों में 23 नए परमाणु बिजलीघर निर्माणाधीन हैं।

केवल तारीफ सुनने, लिखने और पढ़ने वाले लोग अमेरिकी या जर्मन नेताओं के पूरे भाषण पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते, अन्यथा उनका ध्यान अमेरिकी नेताओं द्वारा अपने लोगों को भारत के साथ परमाणु समझौते के पक्ष में दिए जा रहे इस तर्क पर भी जाता कि इस समझौते के क्रियान्वयन से अमेरिका को अरबों रुपयों की लागत वाले परमाणु संयंत्रों-उपकरणों को बेचने का लाभ मिलेगा। ऐसा ही एक बयान महीने भर पहले (24 मार्च, 2006) को अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन रेडमेकर ने दिया था। यही नहीं, उनके मित्र देशों के नेता यूरेनियम निर्यात की संभावनाएं टटोलने भारत आ चुके हैं। मतलब यही कि अपने परमाणु बिजलीघरों को बंद करने की स्थिति में जर्मनी भी फ्रांस, रूस, अमेरिका की तरह अपने परमाणु बिजली संयंत्र या अन्य उपकरण भारत को बेचकर मुनाफा कमाना चाहेगा। जर्मनी के एक बड़े संगठन ने पिछले सप्ताह ही परमाणु ऊर्जा के खतरों से आगाह करते हुए चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से अब तक हो रहे नुकसान का विस्तृत विवरण जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उस दुर्घटना से फैली रेडियो एक्टिविटी से अब भी कम से कम दो लाख 70 हजार लोग कैंसर से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के अनुसार इनमें से करीब 93 हजार की मृत्यु तय है।

परमाणु ऊर्जा के पक्षधरों का तर्क यह रहता है कि ऊर्जा के अन्य प्रमुख स्रोत तेल, गैस और कोयले के भी घातक प्रभाव होते हैं, तेल के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी या ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना ठीक होगा। यह भी कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अधिक कारगर उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन दुर्घटनाएं न होने की शर्तिया गारंटी कोई नहीं दे सकता। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा के बजाय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास क्यों नहीं किए जा सकते। जर्मनी जैसे यूरोपीय देश में तो साल में तीन-चार महीने ही सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। फिर भी सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में जापान के बाद जर्मनी दूसरे नंबर पर है। वहां अब पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर जोर है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में फिलहाल जर्मनी पहले स्थान पर है जबकि स्पेन दूसरे, अमेरिका तीसरे तथा भारत चौथे स्थान पर है। भारत सरकार विदेशों से गिने-चुने परमाणु बिजलीघरों को खरीदने, लगाने और चालू करने में जितने अरब रुपये खर्च करने वाली है, उससे कई गुना कम खर्च में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बल पर भारत के छोटे-छोटे कस्बों और गांवों को सुरक्षित बिजली दी सकती है। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के परमवीर राष्ट्रभक्तों ने परमाणु बम बनाकर दुनिया को डरा दिया और अब कांग्रेस गठबंधन सरकार ने भी उनके पदचिह्नों पर परमाणु बमों और बिजली को देश का सबसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना रखा है। जबकि ऐसे ही नेताओं का एक बड़ा वर्ग सूर्य और पवन देवता के नाम जपते हुए दिन शुरू करता है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले सोनिया गांधी 'पवनपुत्र हनुमान' के मंदिर में अर्चना करने जाती हैं। सत्ता केंद्रों के आध्यात्मिक अथवा गांधीवादी गुरु या सलाहकार मंडली भारत में सौर ऊर्जा की अपार क्षमताओं के उपयोग के लिए व्यापक कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती। केंद्र में सत्ता बदलने पर विभागों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों के नाम और पाठ्यक्रम तक बदल जाते हैं लेकिन किसी 'राम' या 'गांधी' परंपरा वाली सरकार ने अपने 'गैर परंपरागत ऊर्जा' मंत्रालय का नाम नहीं बदला। मेरी समझ से भारत जैसे देश में सूरज अथवा हवा से बिजली बनाने के काम को बढ़ावा देने वाले मंत्रालय का सही नाम 'परंपरागत ऊर्जा' मंत्रालय होना चाहिए। असलियत यह है कि इस मंत्रालय के मंत्री या अफसर अपने को दीन-हीन भी समझते हैं क्योंकि उनके कार्यक्रमों के लिए उपकरणों-संयंत्रों की अरबों रुपयों की खरीद विदेश से नहीं होती। तेल, गैस या परमाणु रिएक्टरों का आयात करने के खेल में भारत का खर्च ही खर्च, लेकिन नेताओं, अफसरों और दलालों के लिए कमाई ही कमाई है। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। जर्मनी की राइन नदी का पानी पीकर लौटे नेता और सलाहकार इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि नए परमाणु बिजली घरों पर अरबों रुपये के खर्च के बजाय भारत में उपलब्ध ऊर्जा के सभी संभव संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग कैसे हो सकता है? भोपाल गैस दुर्घटना कांड और चेरनोबिल परमाणु कांड में हुए हजारों शहीदों को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि भविष्य में कहीं भी लोग इस तरह वर्षों तक तड़प-तड़प कर नहीं मरें। ●

भोपाल एवं चेरनोबिल के हजारों शहीदों को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि कहीं भी लोग इस तरह वर्षों तक तड़प कर नहीं मरें।